



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1995/चैत्र 10, 1917

No. 189] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH, 31, 1995/CHAITRA 10, 1917

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995

कां.आ. 281(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए. 95.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या-320(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए. 79, तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसमें इससे पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) मैसर्स अगोला जिप्सर कर्पना प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और तब, 775 GI/95

बन्द और रूपण उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1995 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समय-समय पर निर्देश जारी किये थे। (देखिये भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश) :

- सं० का०आ० 246(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 25 मई, 1982
 सं० का०आ० 832(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/82, तारीख 24 नवम्बर, 1982
 सं० का०आ० 385(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 31 मार्च, 1983
 सं० का०आ० 872(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 30 नवम्बर, 1983
 सं० का०आ० 472(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 28 जून, 1984
 सं० का०आ० 975(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984
 सं० का०आ० 275(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/85, तारीख 29 मार्च, 1985
 सं० का०आ० 146(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/86, तारीख 31 मार्च, 1986
 सं० का०आ० 266(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/87, तारीख 30 मार्च, 1987
 सं० का०आ० 326(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/88, तारीख 30 मार्च, 1988
 सं० का०आ० 247(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/89, तारीख 31 मार्च, 1989
 सं० का०आ० 277(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/90, तारीख 30 मार्च, 1990
 सं० का०आ० 214(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/91, तारीख 26 मार्च, 1991
 सं० का०आ० 250(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/92, तारीख 30 मार्च, 1992
 सं० का०आ० 219(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/93, तारीख 31 मार्च, 1993
 सं० का०आ० 278(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/94, तारीख 31 मार्च, 1994

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1996 तक की जिसमें यह तारीख भी शामिल है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1996 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अन्तिम के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2/23/80—सां० यु० एस०/आइ० प्रार० ए०]

प्रतिभा करन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi., the 31st March, 1995

S.O. 281(E)|18AA|IDRA|95.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1995 (Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

- Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,
 S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,
 S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st March, 1983,
 S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,
 S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,
 S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,
 S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,
 S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March 1986.

S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,
S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,
S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,
S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,
S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991,
S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92, dated the 30th March, 1992,
S.O. 219(E)|18AA|IDRA|93, dated the 31st March, 1993 and
S.O. 278(E)|18AA|IDRA|94, dated the 31st March, 1994.

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1996.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 18AA read with the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1996.

[F. No. 2(23)|80-CUS|IRS]
PRATIBHA KARAN, Jt. Secy.